चीनी के दाम गिरने से मिलों को भारी नुकसान

PM के दरबार में जाएगा गन्ना किसानों की पेमेंट का मुद्दा

[ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली]

फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान गन्ना किसानों की बकाया रकम का मुद्दा प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के पास ले जाएंगे। पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को गन्ना किसानों की बकाया रकम के भुगतान के लिए हरसंभव कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने बताया, 'केंद्र सरकार को भी शुगर इंडस्ट्री की वित्तीय समस्याओं की जानकारी है और इस वजह से हमने इंडस्ट्री की मदद करने और बकाया रकम के भुगतान के लिए पहले ही बहुत सी कोशिशें की हैं।'

पासवान ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी, राज्यों के मंत्रियों और चीनी का प्रॉडक्शन करने वाले राज्यों के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद यह बात कही।

चीनी मिलों का कहना है कि गन्ने की बकाया रकम मौजूदा सीजन में 1,93,000 करोड़ रुपये की है और स्थिति चिंताजनक है। इससे निपटने के लिए जल्द कदम उठाने की जरूरत है।

एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना था कि मिलों को दी गई सहायता का इस्तेमाल किसानों को सीधे भुगतान के लिए किया जाना चाहिए। उनका कहना था, 'चीनी का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए और इसके इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाकर 40 पर्सेंट करनी चाहिए ताकि हम इंपोर्ट को रोक सकें।'

पासवान ने बताया कि मीटिंग में चीनी का बफर स्टॉक बनाने, एथनॉल प्रॉडक्शन को बढ़ावा देने और मिलों के मॉडर्नाइजेशन जैसे सुझाव दिए गए। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों ने कहा कि मिलों को शीरे से सीधे एथनॉल के प्रॉडक्शन की छूट मिलनी चाहिए। शुगर सेक्टर को उपलब्ध कराए जा रहे इंटरेस्ट फ्री लोन की

चीनी का प्रॉडक्शन करने वाले राज्यों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह और विमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट मिनिस्टर मेनका संजय गांधी

> केंद्र को भी शुगर इंडस्ट्री की वित्तीय समस्याओं की जानकारी है और इस वजह से हमने इंडस्ट्री की मदद करने और बकाया रकम के भुगतान के लिए पहले ही बहुत सी कोशिशें की हैं
>
> **राम विलास पासवान**
> फूड मिनिस्टर

रीस्ट्रक्चरिंग का भी सुझाव दिया गया। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के मुताबिक, 15 अप्रैल तक देशभर की चीनी मिलों ने 2.63 करोड़ टन चीनी का प्रॉडक्शन किया था। 2014 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 2.31 करोड़ टन का था। एसोसिएशन को उम्मीद है कि इस वर्ष प्रॉडक्शन बढ़कर 2.7 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा और चीनी की घरेलू खपत 2.48 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

पिछले छह महीनों में चीनी के डोमेस्टिक एक्स-मिल प्राइसेस में आठ-नौ रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। अभी ये उत्तर प्रदेश में 25-25.50 रुपये प्रति किलोग्राम और महाराष्ट्र में 21 रुपये प्रति किलोग्राम हैं। एसोसिएशन ने बताया, 'चीनी के दाम पिछले सात वर्षों के सबसे निचले स्तर पर हैं। ये 7,000-9,000 रुपये प्रति टन की प्रॉडक्शन कॉस्ट से भी नीचे चले गए हैं।'

मिलों का कहना है कि 30-35 लाख टन चीनी बिकने पर ही किसानों की बकाया रकम चुकाई जा सकेगी। इसके अलावा चीन के एक्स-मिल प्राइसेज भी उस लेवल पर पहुंचने चाहिए जो मौजूदा शुगर सीजन की शुरुआत में थे।

इकनॉमिक टाइम्स
17/4/15